

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-265

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग एवं आपूर्ति

\*265. श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में काफी अंतर है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में अत्यधिक अंतर व्याप्त है जो अखिल भारतीय औसत से भी ज्यादा है तथा दो-तीन छोटे राज्यों के अलावा देश में सर्वाधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सर्वाधिक मांग-आपूर्ति अंतर राज्य-वार कितना है;
- (ग) क्या सरकार का लोड शेडिंग हेतु विद्युत वितरण कंपनियों पर भारी अर्थदंड लगाने तथा राज्यों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को राजसहायता का सीधे अंतरण किये जाने हेतु प्रावधान करने के लिए विद्युत अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं; और
- (घ) क्या सरकार द्वारा पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों में ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति किये जाने के कारण विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत की मांग एवं आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 265 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : राज्य द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 2019-20 (जून, 2019 तक) के दौरान वैद्युत ऊर्जा और व्यस्ततम मांग के संबंध में उत्तरप्रदेश सहित अपने देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति के ब्यौरे अनुबंध में दिये गये हैं। 0.6% व्यस्ततम विद्युत की कमी के अखिल भारत औसत के मुकाबले पश्चिम बंगाल में कोई व्यस्ततम कमी नहीं है, और इसके अतिरिक्त जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 0.4% ऊर्जा की कमी है, पश्चिम बंगाल में ऊर्जा की कमी 0.3% है।

(ग) : विद्युत अधिनियम के संशोधनों को अंतिम रूप दिये जाने के लिए अनावश्यक लोडशेडिंग के लिए विद्युत वितरण कम्पनियों पर शास्तियां लगाने का प्रस्ताव करने तथा राज्यों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी अन्तरण करने संबंधी प्रावधान करने वाले मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।

(घ) : चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 107.3 मिलियन टन (एमटी) की तुलना में विद्युत संयंत्रों में कोयले की कुल प्राप्त 112.0 मिलियन टन थी जो 4.3% की वृद्धि दर्शाती है। विद्युत मंत्रालय, कोयला और रेल मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से दैनिक आधार पर सीईए द्वारा निगरानी किए गए विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयले के स्टॉक में 04.07.2019 की स्थिति के अनुसार 26.09 एमटी तक का सुधार हुआ है जो पिछले वर्ष के इसी दिन को दस दिनों के लिए 15.5 एमटी की तुलना में 15 दिन के उत्पादन के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में हुई वृद्धि के कारण विद्युत ग्रिड में विद्युत की मांग की पूर्ति ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा की जा रही है तथा अन्य उत्पादन स्रोतों द्वारा सहायता की जाती है।

एक अन्तर-मंत्रालयी उप-समूह जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय, सीईए, सीआईएल तथा एससीसीएल के प्रतिनिधि शामिल हैं, नियमित आधार पर कोयले की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करता है। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर, सीआईएल/एससीसीएल कोयले की आपूर्ति का संवर्धन करते हैं तथा रेलवे कम कोयला स्टॉक वाले विद्युत संयंत्रों को रैकों की आपूर्ति को प्राथमिकता देता है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत की मांग एवं आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 265 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2019-20 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2019 - जून, 2019*				अप्रैल, 2019 - जून, 2019*			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	500	500	0	0.0	413	413	0	0.0
दिल्ली	9,904	9,899	5	0.0	6,904	6,904	0	0.0
हरियाणा	14,420	14,420	0	0.0	10,237	10,237	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,541	2,523	19	0.7	1,619	1,619	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	5,043	4,166	877	17.4	3,033	2,426	607	20.0
पंजाब	15,315	15,309	6	0.0	13,090	13,090	0	0.0
राजस्थान	20,856	20,835	21	0.1	12,620	12,620	0	0.0
उत्तर प्रदेश	36,022	35,804	218	0.6	22,487	22,057	430	1.9
उत्तराखंड	3,861	3,778	84	2.2	2,164	2,164	0	0.0
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>108,462</b>	<b>107,233</b>	<b>1,229</b>	<b>1.1</b>	<b>65,950</b>	<b>64,838</b>	<b>1,112</b>	<b>1.7</b>
छत्तीसगढ़	8,315	8,314	1	0.0	4,596	4,574	22	0.5
गुजरात	31,725	31,725	0	0.0	18,437	18,424	13	0.1
मध्य प्रदेश	18,994	18,994	0	0.0	10,187	10,180	7	0.1
महाराष्ट्र	42,724	42,724	0	0.0	23,621	23,613	8	0.0
दमन व दीव	660	660	0	0.0	351	350	1	0.2
दादरा नागर हवेली	1,637	1,637	0	0.0	824	824	0	0.0
गोवा	1,158	1,158	0	0.0	622	621	1	0.1
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>105,213</b>	<b>105,212</b>	<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>57,113</b>	<b>57,093</b>	<b>20</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	17,427	17,413	14	0.1	10,170	10,170	0	0.0
तेलंगाना	15,565	15,563	2	0.0	10,269	10,202	67	0.7
कर्नाटक	19,363	19,360	3	0.0	12,700	12,688	12	0.1
केरल	7,067	7,052	15	0.2	4,487	4,300	186	4.2
तमिलनाडु	29,828	29,825	3	0.0	15,680	15,668	11	0.1
पुडुचेरी	787	786	1	0.1	464	462	2	0.5
लक्षद्वीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>90,037</b>	<b>89,999</b>	<b>38</b>	<b>0.0</b>	<b>49,218</b>	<b>49,103</b>	<b>115</b>	<b>0.2</b>
बिहार	8,705	8,700	6	0.1	5,754	5,754	0	0.0
झीवीसी	5,685	5,683	2	0.0	3,118	3,118	0	0.0
झारखंड	2,272	2,254	18	0.8	1,396	1,389	6	0.5
ओडिशा	7,937	7,937	0	0.0	5,207	5,207	0	0.0
पश्चिम बंगाल	15,120	15,076	44	0.3	9,115	9,115	0	0.0
सिक्किम	121	121	0	0.0	99	99	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	87	81	6	6.7	58	54	4	7
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>39,841</b>	<b>39,772</b>	<b>69</b>	<b>0.2</b>	<b>24,113</b>	<b>24,113</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
अरुणाचल प्रदेश	190	188	2	1.1	146	144	2	1.4
असम	2,541	2,354	187	7.3	1,935	1,791	144	7.4
मणिपुर	206	204	2	1.0	197	188	9	4.8
मेघालय	500	481	19	3.8	367	367	0	0.0
मिजोरम	147	145	2	1.4	116	113	3	2.8
नागालैंड	190	188	2	1.1	157	140	17	11.0
त्रिपुरा##	446	432	14	3.2	320	311	9	2.8
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>4,218</b>	<b>3,992</b>	<b>226</b>	<b>5.4</b>	<b>2,922</b>	<b>2,861</b>	<b>61</b>	<b>2.1</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>347,771</b>	<b>346,208</b>	<b>1,563</b>	<b>0.4</b>	<b>183,673</b>	<b>182,533</b>	<b>1,140</b>	<b>0.6</b>

\* अंतिम

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

##बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

\*\*\*\*\*